

दि कार्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 7, अंक : 31

(प्रति बुधवार), इन्दौर 23 मार्च 2022 से 29 मार्च 2022

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

एक ऐसा गांव जिसमें इमली के पेड़ों से आंकी जाती है जीडीपी

चित्तपुर चित्तपुर गांव में रहने वाले हर आदमी की जिंदगी में थोड़ा सा इमली का पेड़ शामिल है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के इस गांव में इमली का पेड़ एक जीवंत मुद्रा है, जो लोगों की किस्मत तय करता है।

हालांकि गांव में कोई सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में नहीं जानता लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता है कि किसी साल गांव की जीडीपी, इसी पर निर्भर करती है कि उस साल बाजार में इमली का मूल्य कितना है। आठ सौ घरों वाले इस गांव में 1700 इमली के पेड़ हैं। गांव के लोग एक-दूसरे की आर्थिक-स्थिति इसी से तय करते हैं कि किसी के पास इमली के पेड़ कितने हैं। इस गांव में इस तरह की खबरों को काफी आर्थिक महत्व है कि किसके इमली के पेड़ पर कितने फल आए हैं, हाल ही में लगाए गए इमली के पौधे किस गति से बढ़ रहे हैं और कौन से पेड़ बूढ़े होने के चलते सूखने लगे हैं। कभी-कभी तो इमली के पेड़ों का जायजा लेने के लिए ग्रामसभा की बैठक भी बुलाई जाती है। 21 फरवरी की सुबह युवाओं का एक समूह गांव में इमली के पेड़ों का हाल-चाल लेने निकला है। इनमें से ज्यादातर काम के लिए केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर चुके हैं। प्रवासी मजदूर होने का दर्द अभी भी उनके चेहरों पर है। दो साल पहले कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में ये सारे गांव लौटे थे। यहां लौटने के बाद यह इमली के पेड़ ही थे, जिन्होंने इन युवाओं को फिर से जिंदगी की योजना बनाने में मदद की। आमतौर पर फरवरी से इमली के पेड़ों पर कलियां आनी शुरू हो जाती हैं लेकिन इस साल ज्यादातर पेड़ों पर वे नजर नहीं आ रही हैं। यहां लोग ये मानते हैं कि जिस साल आम ज्यादा होते हैं, उस साल इमली कम फलती है। इसे लोगों की मान्यता के अलावा पारिस्थितिक संकेतों पर टिका स्थानीय विश्वास भी कह सकते हैं, जो सालों से इमली के पेड़ों को

देखने के उनके अनुभव से जन्मा है। गौरतलब है कि इस साल जनवरी के अंत से ही यहां आम के पेड़, बौर से भरे नजर आने लगे हैं। इमली की कलियां न दिखने से गांव के रहने वाले लकमू कश्यप चिंतित हैं। वह कहते हैं- 'जब किसी की ज्यादातर आमदनी इमली के पेड़ों पर टिकी हो तो कलियां न आने से उसकी हालत तो खराब होगी ही। इस साल कुछ परिवारों को गरीबी झेलनी पड़ेगी।' इमली के पेड़ों का प्रति व्यक्ति स्वामित्व इस गांव में गरीबी रेखा को परिभाषित करता है। इस साल के लिए लकमू का आकलन ऐसा था, जैसे गांव की मुद्रा गिरते ही लोग गरीबी रेखा से नीचे गिर रहे हों। चित्तपुर गांव की भौगोलिक स्थिति कई ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी रही है, ऐसी घटनाएं, जिन्होंने गांव के अस्तित्व को चुनौती दी हो। ऐसी ही एक घटना गांववालों के दिल में बसी है, जिसके चलते वे इमली के पेड़ों को अपने अस्तित्व का केंद्र-बिंदु मानते हैं। बहुत साल पहले इस गांव का नाम धनी करका था, जो बाद में बदलकर चित्तपुर हो गया। उस साल, जब गांव में ब्रिटिश शासन लागू था और जिसका यहां एक थाना भी था। उसी साल गांव में तेंदुए आए, जिनके डर से गांववालों को गांव छोड़ना पड़ा। कई सालों के बाद वे वापस गांव लौटे और अपने पूर्वजों के गांव को को नया नाम दिया - चित्तपुर, यानी तेंदुओं का गांव। उसी के बाद गांववालों ने इमली की कीमत समझी। कई लोग अपने पूर्वजों के मुंह से सुनी कहानियां याद करते हैं। इनमें से कई कहानियां ऐसी हैं, जिनमें इमली का पेड़ उस धुरी के रूप में दिखाई देता है, जिसके चारों ओर धरवा जनजाति के लोग



फिर से जीवित हो जाते हैं। लोगों को खाना देने के लिए यहां खेती नहीं थी लेकिन प्रचुर मात्रा में होने वाले इमली के पेड़ों ने गांववालों को संभाल लिया। जल्दी ही यह मुख्य भोजन बन गई। खेती करने लायक स्थितियां होने तक इमली का गुदा और इसके कोमल पत्ते लोगों के खाने के काम आने लगे। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए काम करने वाले स्थानीय ठेकेदारों ने गैर-लकड़ी बनोपज की भोजन के तौर पर इमली से अदला-बदली शुरू कर दी। आखिरकार स्थानीय सामाहिक बाजार में भी चित्तपुर की इमली का आगमन हुआ। दो रूपों में - पहला, बेचने के लिए एक उत्पाद के रूप में और दूसरा, ऐसी मुद्रा के तौर पर भी, जिससे खाने की दूसरी चीजें खरीदी जा सकें। 28 साल के वीडियोग्राफर लकमू नाग, जो जिले के एक लोकल टीवी चैनल को स्थानीय घटनाओं की फुटेज भेजते हैं, उनके मुताबिक, 'यहां हर किसी को विरासत में इमली का एक पेड़ मिलता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पूर्वज गरीब थे या अमीर। अगर यह पेड़ फलता है तो वह आदमी अमीर होता जाता है। अगर कोई ज्यादा पेड़ लगाता है तो उसकी जिंदगी सुधरती चली जाती है और अगर कोई अपने पेड़ों की उपेक्षा करता है तो उसे जिंदा रहने के लिए प्रवासी बनने का रास्ता

चुनना पड़ता है, जो आखिरी रास्ता है।' लकमू खुद भी एक टीवी पत्रकार से ज्यादा इमली इकट्ठा करने वाले ग्रामीण हैं। वह कहते हैं, 'हमारे गांव और आसपास के इलाके में इमली के पेड़ से जुड़े कामों का स्थानीय महत्व है। यहां ऐसे कार्यक्रम कम हैं, जिन्हें रिकॉर्ड कर मैं चैनल में भेज सकूँ, जिस वजह से मैं ज्यादा कमा नहीं पाता।' उनकी पुश्तैनी जमीन और रियासत में इमली के करीब बीस पेड़ हैं। अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में देने के लिए लकमू ने खुद भी पांच पेड़ लगाए हैं। वह झंपते हुए कहते हैं - 'इन इमली के पेड़ों की बदौलत मैं लखपाति हूँ।' चित्तपुर जैसे गांवों ने ही बस्तर जिले को इमली के वैश्विक व्यापार का मुख्य केंद्र बना दिया है। इसका जिला मुख्यालय जगदलपुर, एशिया का सबसे बड़ा इमली का बाजार है, जहां से वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सालाना पांच सौ करोड़ का कारोबार होता है। यहां से 54 देशों को इमली भेजी जाती है। आदिवासी समुदायों के साथ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजू राना के मुताबिक, 'बस्तर क्षेत्र में वनोत्पाद, आय के सबसे बड़े स्रोत हैं। खासतौर से इमली, जिससे गरीब की अच्छी आमदनी हो जाती है।' 2019 में कृषि विज्ञान केंद्र बस्तर द्वारा प्रकाशित

सर्वेक्षण के मुताबिक, इमली का उत्पादन करने वालों में से करीब 43 फीसदी लोग 35 साल से कम उम्र के थे। इनमें से ज्यादातर को इस काम का बीस साल का तर्जुबा है। लकमू नाग कहते हैं, - 'इमली का काम हमारे लिए पैसा कमाने का कुदरती जरिया है, जिसे हम अपने पूर्वजों से हासिल करते हैं। हम इस काम की दक्षता हासिल करते हैं, साथ ही बाजारों में मोल-भाव करने की कला भी।' वह आगे कहते हैं, - 'युवा लोग वनोत्पाद का कारोबार करना पसंद करते हैं। वैसे भी जिसके पास जमीन जितनी कम होगी, उसकी इमली पर निर्भरता उतनी ज्यादा होगी।' नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी-सूचकांक में बस्तर की 47 फीसदी आबादी बहुआयामी गरीब है। जिले की 70 फीसदी आबादी अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित है और ज्यादातर जंगलों में और आसपास रहती है। उनकी नकद आय का लगभग 70 फीसदी बनोपज से आता है। यह देश के 115 पिछड़े जिलों की सूची में शामिल है, और 1950 के दशक से सबसे गरीब जिलों में से एक रहा है। समय के साथ इमली, चित्तपुर की अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने लगी है। सुनिश्चित किया कि लोग गांव से बाहर न जाएं।

मौसम का मिजाज - उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी, कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार

नई दिल्ली। आज पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू या हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है। वहीं आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और 31 मार्च से 03 अप्रैल के दौरान इन्हीं क्षेत्रों के अलग-अलग हिस्सों में लू या हीट वेव चलने के आसार हैं।

आज दक्षिण हरियाणा और दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में भीषण लू या हीट वेव की आशंका है। आज यानी 30 मार्च को जम्मू और हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लू या हीट वेव का अनुमान है। 30 मार्च से 03 अप्रैल के दौरान झारखंड और आंतरिक ओडिशा, 31 मार्च और 01 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों में लू चलने के आसार हैं। 31 मार्च से 03 अप्रैल के दौरान छत्तीसगढ़ में 01-03 अप्रैल के दौरान गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में लू चलने की आशंका बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद, निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तरों में बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर राज्यों तक 40 से 50 किमी प्रति घंटे की दर से तेज दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के चलने के आसार हैं। उपरोक्त मौसम संबंधी गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि 31 मार्च से 03 अप्रैल के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों में बिजली गिरने, तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। 31 मार्च और 01 अप्रैल को असम और



मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तरों पर हवा के रुकने के कारण अगले 5 दिनों के दौरान केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, लक्षद्वीप, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान केरल और माहे के अलग-अलग हिस्सों में गरज के साथ बौछरें पड़ने तथा बिजली गिरने के आसार हैं। कल पश्चिम राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू महसूस की गई, वहीं पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में, दिल्ली के कुछ हिस्सों में, दक्षिण हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों में और हिमाचल प्रदेश में भी लू चली। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में लू महसूस की गई। कल जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद,

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिम राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया। वहीं कल झारखंड के अधिकांश इलाकों, गुजरात, विदर्भ और मराठवाड़ा के कई हिस्सों, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल में गंगा के अलग-अलग तटीय इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस से 5.0 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। कल छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों, कोंकण और गोवा, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक के कई हिस्सों, केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3.0 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया।

कल उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से -1.6 डिग्री सेल्सियस से -3.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कल देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा। कल पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान और बिहार के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया। वहीं कल पंजाब और तटीय कर्नाटक के कई हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, असम और मेघालय, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों और मध्य महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस से 5.0 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। कल गुजरात के अधिकांश इलाकों, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, कोंकण और गोवा के कई हिस्सों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग-अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से -1.6 डिग्री सेल्सियस से -3.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कल देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहा।

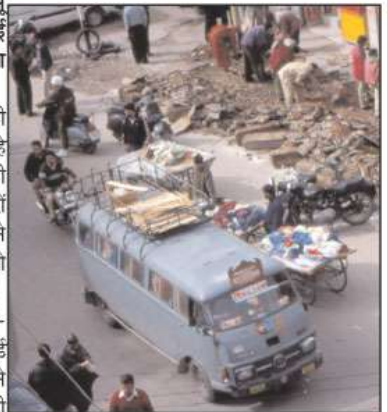
साभार - डाउन टू अर्थ

बाणगंगा में प्रदूषण - एनजीटी ने कहा प्राधिकरण जल्द से जल्द उठाएं रोकथाम के कदम

मुंबई। जम्मू-कश्मीर के कटरा में बाणगंगा नदी में प्रदूषण के बचाव को लेकर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। बाणगंगा नदी जम्मू के कटरा कस्बे के लिए पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के बावजूद प्रशासन के जरिए इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इस शिकायत और प्राधिकरणों की रिपोर्ट के बाद कहा है कि बाणगंगा में प्रदूषण रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वह नाकाफी और अस्पष्ट हैं।

एनजीटी ने हिमाशु शर्मा बनाम जम्मू-कश्मीर संघ के मामले में 23 मार्च, 2022 को अपने आदेश में कहा कि हमने पेश की गई रिपोर्ट्स में पाया है कि बाणगंगा में डिस्चार्ज छोड़ने वाले एसटीपी का प्रदर्शन कितना कारगर है। नदी में एसटीपी से छोड़े जा रहे शोधित सीवेज की गुणवत्ता और मात्रा को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। जरूरत है कि नदी में डिस्चार्ज से पहले शोधित सीवेज की गुणवत्ता की जांच परख स्पष्ट और पारदर्शी हो। इसके अलावा यह भी आवश्यकता है कि वेस्ट सेग्रिगेशन के सेंटर नदी किनारों से एक उचित दूरी पर मौजूद हों। इसके अलावा 1.2 और 4.4 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी के प्रस्तावित साइट भी उचित होने चाहिए। पीट ने कहा कि आवश्यकता है कि आर्मी की बस्तियों से सीवेज इफ्लुएंट, शूकरों की शिपिंग, खच्चरों के शोड व बायो गैस प्लांट को सही से प्रबंधित किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह का प्रदूषण नदी में न जाने पाए।

इसके अलावा रिसाइकल होने वाले कचरे को सही केंद्रों पर पहुंचाया जाएगी। वहीं, 101757 घन मीटर लीगैसी वेस्ट की बायो-माइनिंग और अतिक्रमण को भी रेग्युलेट किया जाए। पीट ने कहा है कि कटरा नगर निकाय और कटरा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड समस्या के समाधान के लिए उचित कानूनी कदम उठाएं। जो भी हर्जाना एकत्र हो उसका इस्तेमाल रेरेटोरेशन में किया जाए। पीट ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन की जरूरत को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं यह ध्यान रहे कि राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों को साफ पर्यावरण मुहैया कराए। ऐसे में कचरा प्रबंधन की दिशा में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। डीपीआर के फंड को जल्द से जल्द आवंटन दिया जाए।



जल्द से जल्द उठाएं रोकथाम के कदम

तो क्या आर्थिक खुशहाली के लिए बर्बाद किए जा रहे हैं जंगल, अध्ययन से उठा सवाल

नई दिल्ली। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स द्वारा किए अध्ययन से पता चला है कि वित्तीय संकट की वजह से वनों के बढ़ते विनाश की दर में करीब 36 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है। अपने इस अध्ययन में वनों के बढ़ते कटाव पर वित्तीय संकट के प्रभाव को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने 21वीं सदी के दौरान 2001 से 2017 के बीच 150 देशों में आए 100 से भी ज्यादा वित्तीय संकटों और वनों के विनाश सम्बन्धी आंकड़ों का विश्लेषण किया है।

शोध में वन विनाश सम्बन्धी आंकड़े ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (जीएफडब्ल्यू) द्वारा उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित हैं। इतना ही नहीं, जर्नल सस्टेनेबिलिटी साइंस में प्रकाशित इस शोध से यह भी पता चला है कि न केवल इसकी वजह से वन विनाश की दर में गिरावट दर्ज की गई है साथ ही इसकी वजह से वनों की कटाई को प्रेरित करने वाले कारकों जैसे टिम्बर, पाम आयल, मवेशी, सोयाबीन, कॉफी, कोको उत्पादन आदि में भी गिरावट देखी गई थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक हालांकि वैश्विक स्तर पर वित्तीय अस्थिरता के चलते वन विनाश में गिरावट दर्ज की गई थी, पर गिरावट की यह दर अलग-अलग क्षेत्रों के आधार पर भिन्न-भिन्न थी। गौरतलब है कि अस्थिरता के इस दौर में एशिया, अफ्रीका स्थित और वित्तीय रूप से कमजोर देशों में इसका प्रभाव कहीं ज्यादा व्यापक था। पता चला है कि वित्तीय संकट कम आय वाले देश में वन विनाश की दरों को कहीं अधिक प्रभावित करेगा, क्योंकि उन देशों में

ज्यादातर वन विनाश वस्तुओं की मांग पर आधारित होता है। शोध के मुताबिक जहां फनीचर के लिए उपयोग होने वाली राउंडवुड में वित्तीय संकट के दौरान 6.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं मवेशियों में 2.3 फीसदी और कोको उत्पादन में भी 8.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। यदि क्षेत्रीय तौर पर देखें तो जहां वित्तीय संकट की वजह से एशिया में होते वन विनाश में 83 फीसदी की गिरावट आई थी वहीं अफ्रीका में यह गिरावट 43 फीसदी और यूरोप में 22 फीसदी गिरावट देखी गई थी। कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर वित्तीय संकट के चलते 2001 से 2017 के बीच वनों की कटाई में 36 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं यदि देशों की आय के आधार पर देखें तो जहां वित्तीय संकट के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर देशों में वनों की कटाई में 51 फीसदी की गिरावट आई थी वहीं मध्यम से उच्च आय वाले देशों में यह गिरावट 39 फीसदी और उच्च आय वाले देशों में केवल 18 फीसदी ही थी। देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र ने भी वित्तीय संकट को वैश्विक विकास के एजेंडे के लिए खतरा माना है। हमें समझना होगा कि हम पर्यावरण पर बढ़ते प्रभाव को सीमित करने के लिए केवल आर्थिक गतिविधियों में कमी के भरोसे नहीं रह सकते। इस बारे में शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता अलेक्जेंडर एस एंटोनारकिस का कहना है कि हम वित्तीय उछाल के दौर में पर्यावरण का शोषण नहीं कर सकते। हमें हमारे मौजूदा आर्थिक मॉडल के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। इसके लिए हमें ऐसे आर्थिक मॉडल की

जरूरत होगी जिसमें शाश्वत विकास और इकोसिस्टम को बनाए रखने पर जोर दिया गया हो। उनके अनुसार ऐसा ही कुछ कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिला था जब आर्थिक गतिविधियों में आई कमी के चलते पर्यावरण को दोबारा फैलने फूलने का मौका मिला था। लॉकडाउन के कारण दुनिया के कई देशों में थोड़े समय के लिए ही सही वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि महामारी ने पर्यावरण के क्षेत्र में हुई प्रगति को पलट दिया है। भूमि क्षरण अभी भी जारी है, बढ़ी संख्या में जीवों और प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही बेतहाशा उत्पादन और खपत अभी भी जारी है। उनके अनुसार जो निष्कर्ष सामने आए हैं वो वित्तीय संकट के दौरान वन-विनाश में आई एक अस्थायी राहत की ओर इशारा करते हैं। फिर भी वनों के शाश्वत विकास के लिए वन प्रबंधन को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे आर्थिक विकास और संसाधनों के बढ़ते हनन के बीच की कड़ी को तोड़ा जा सके। साथ ही संकट से उबरने के बाद भी यह अवधारणा राष्ट्रीय एजेंडा से अलग न हो इसका ध्यान रखना होगा।

10 करोड़ हेक्टेयर प्रति दशक की दर से नष्ट हो रहे हैं जंगल-यदि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट्स के आंकड़ों को देखें तो दुनिया में 31 फीसदी से ज्यादा भूमि पर वन हैं। जो न केवल जैवविविधता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन बल्कि साथ ही खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। यह जंगल

पेड़-पौधों की अनगिनत प्रजातियों का घर हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह जंगल उभयचर जीवों की करीब 80 फीसदी, पक्षियों की 75 फीसदी और स्तनपायी जीवों की 68 फीसदी प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं यह वन खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के असर को भी सीमित करने में मदद करते हैं। वहीं यदि इन जंगलों के बढ़ते विनाश की बात करें तो 1990 से लेकर अब तक करीब 42 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं, जिसके लिए भूमि उपयोग में तेजी से आता बदलाव जिम्मेवार है। जिस तरह से कृषि और शहरों का विस्तार हो रहा है उसके चलते इन वनों का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। पता चला है कि 2015 से 2020 के बीच दुनिया भर में वन क्षेत्र एक करोड़ हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से नष्ट हो रहे हैं। हालांकि वन विनाश की यह दर 90 के दशक में 1.6 करोड़ हेक्टेयर प्रति वर्ष थी। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2017 से 30 के लिए वनों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक योजना बनाई है। जिसका मकसद स्थाई वन प्रबंधन को बढ़ावा देना और 2030 के सतत विकास के लक्ष्यों में वनों और वृक्षों के योगदान को बढ़ावा देना है। इसके तहत 2030 तक वन क्षेत्र में 3 फीसदी का इजाफा करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में वनों के बढ़ते विनाश को रोकने के लिए दुनिया के 105 देशों ने 'ग्लोबल लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स एंड लैंड यूज' पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे इन जंगलों को बचाया जा सके।

सामार - डाउन टू अर्थ

दिल्ली में नष्ट होते जलनिकायों पर एनएचआरसी ने अधिकारियों को नोटिस देकर मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली में जलनिकायों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए चिंता जाहिर की है। एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के उपाध्यक्ष को छह सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी किया है।

एनएचआरसी ने जिस मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया उसमें कहा गया है कि अधिकारियों द्वारा कथित अनियोजित विकास और लापरवाही के कारण दिल्ली में जल निकाय गायब हो रहे हैं। मसलन दिल्ली ने कथित तौर पर विभिन्न प्राधिकरणों से संबंधित 1,043 जल निकायों की पहचान की है और रिपोर्ट किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उनमें से 169 का या तो उल्लंघन किया गया है या नष्ट कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में खिचड़ीपुर क्षेत्र के एक जलाशय का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे वर्षों पहले शामिल किया गया है लेकिन अभी तक इसे जीवंत नहीं किया गया है। यह भी उल्लेख है कि इन 169 अतिक्रमित जलाशयों में से कुल 103 दिल्ली विकास प्राधिकरण के थे। डीडीए के पास कथित तौर पर 836 जल निकाय हैं, जो शहर में सबसे अधिक संख्या है, इसके बाद राजस्व विभाग है, जिसके दायरे में कुल 131 हैं। मीडिया

रिपोर्ट में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के हवाले से बताया गया है कि 1997 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली में 1,000 जलाशय थे, लेकिन वर्तमान में 700 से भी कम रह गए हैं। आयोग ने कहा कि पर्यावरण के ऐसे महत्वपूर्ण घटकों की सुरक्षा के लिए कानून और दिशानिर्देश मौजूद हैं। अधिकारियों द्वारा कथित लापरवाही मानवाधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि जल निकाय और आर्द्रभूमि जल विज्ञान चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र जैसे जल भंडारण, जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव नियंत्रण और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के साथ माइक्रोक्लाइमेट विनियमन आदि का समर्थन करते हैं। यह शहरी बाढ़ को कम करने में भी मदद करता है। आयोग ने यह भी नोट किया है कि 23 अप्रैल 2019 को आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए दिल्ली में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया था। जबकि जल निकाय जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, या तो कंत्राट पर अतिक्रमण कर लिया गया है या सीवेज से प्रदूषित कर दिया गया है।



सामार - डाउन टू अर्थ



वैज्ञानिकों ने कृत्रिम ओलों के द्वारा लगाया मौसम का सटीक पूर्वानुमान

बर्फ के कण या ओले तब पिघल जाते हैं जब वे नीचे की ओर गर्म हवा की परतों से गुजरते हैं, बड़ी ठंडी बारिश की बूंदें अक्सर अत्यधिक वर्षा होने के पीछे के कारण होते हैं। मौसम के रिकॉर्ड बताते हैं कि अत्यधिक प्राकृतिक घटनाएं जैसे सूखा, भारी वर्षा और ओलावृष्टि भी जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के अधिकतर हिस्सों में और भी अधिक बार हो सकती हैं। चरम मौसम की इन घटनाओं के परिणाम और भी विनाशकारी हो सकते हैं। ओलावृष्टि, फसलों, वाहनों और इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है और साथ ही यह मनुष्यों और जानवरों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इस प्रकार यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब मौसम मॉडल ऐसी किसी भी वर्षा की संभावना और सीमा का सटीकता से अनुमान लगाने में सक्षम होता है। अध्ययनकर्ताओं ने कहा इसके लिए संख्यात्मक मौसम मॉडल बादलों में भौतिक प्रक्रियाओं की सटीक रूप से तैयार की गई गणितीय व्याख्याओं पर आधारित होनी चाहिए।

गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में जेजीयू में वर्टिकल विंड टनल, जो दुनिया में अपनी तरह का इकलौती टनल है और मौसम के संबंध में नए प्रयोगों के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्रदान कर रही है। यह एक 3डी प्रिंटर द्वारा बनाए गए कृत्रिम ओलों का उपयोग करके किया जा रहा है। जेजीयू में इंस्टीट्यूट ऑफ एटमोस्फेरिक फिजिक्स (आईपीए) के डॉ. मिक्लोस स्जाकल ने बताया कि एक बात जो हमने अब तक सीखी है, वह यह है कि यह ओलों का वह रूप है जो प्रभाव से पहले उनके वेग को निर्धारित करता है। डॉ. स्जाकल की टीम यह प्रदर्शित करने में सफल रही है कि लोब वाले ओले कम गतिज ऊर्जा विकसित करते हैं और इस प्रकार एक चिकनी सतह के साथ ओलों की तुलना में कम विनाशकारी क्षमता विकसित करते हैं। ओला और ग्रेपेल, जो कि छोटे, नरम बर्फ के छरों की तरह होते हैं, ये तब बनते हैं जब पानी की बूंदें तूफानी बादलों के भीतर जम जाती हैं। इस ठंडे होने की प्रक्रिया को इन बादलों में उथल-पुथल और जटिल भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा बढ़ावा दिया जाता है जो बहुत अधिक ऊंचाई तक फैल सकते हैं। ये बर्फ के कण तब पिघल जाते हैं यदि वे नीचे की ओर गर्म हवा की परतों से गुजरते हैं। बड़ी ठंडी बारिश की बूंदें हैं जो अक्सर अत्यधिक वर्षा होने के पीछे के कारण होते हैं। यह मानते हुए कि बर्फ के कणों के जमीन पर पहुंचने से पहले पूरी तरह से नहीं पिघलते हैं, वे ओलों या ग्रेपेल के रूप में जाने जाते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम ओलों के साथ प्रयोग-बादलों के आंतरिक भाग की स्थितियां इन जमी हुई बूंदों के विशिष्ट रूप, आकार और द्रव्यमान को

निर्धारित करती हैं। अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि प्राकृतिक ओलों के साथ हमारे प्रयोगों में, हमने देखा है कि वे बारिश की बूंदों के रूप में पिघलते हैं जो व्यास में कई मिलीमीटर तक हो सकते हैं। पिघलने की प्रक्रिया के दौरान बड़े ओले भी फट सकते हैं, जिससे कई छोटी पानी की बूंदें बनती हैं। रिकॉर्ड किए गए मापों से, उनकी टीम उन मापदंडों का अनुमान लगाने या एक्सट्रपलेशन में सक्षम थी, जिनका उपयोग वे कंप्यूटर मॉडल में बादलों के संख्यात्मक सिमुलेशन और वर्षा के लिए मुख्य तत्वों के रूप में कर सकते थे। मैन्ज की शोध टीम ने प्रयोगशाला में जमे हुए पानी से ओले और ग्रेपेल कणों का उत्पादन किया। वास्तविक तापमान और आर्द्रता की स्थिति को बनाए रखते हुए, शोधकर्ताओं ने बारीकी से देखा कि ये ऊर्ध्वाधर हवाओं की सुरंग में कैसे गिरे या पिघले। इसके अलावा, उन्होंने अपने प्राकृतिक समकक्षों पर आधारित कृत्रिम ओलों और ग्रेपेल छरों को बनाने के लिए एक 3डी प्रिंटर का उपयोग किया। यहां तक कि सामग्री घनत्व भी बर्फ के अनुरूप थी। उन्होंने इनका उपयोग अवरोही वस्तुओं के मुक्त रूप से निचे गिरने के गुणों को मापने के लिए किया, ऐसे कारक जो अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में सूक्ष्म भौतिक प्रक्रियाओं के काफी अनुरूप हैं। छह मीटर ऊंची हवा की सुरंग में कृत्रिम रूप से निर्मित ऊर्ध्वाधर वायु धारा में ओलों और ग्रेपेल छरों को स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया था। उनके व्यवहार को उच्च गति और इन्फ्रारेड कैमरों और विशेष रूप से विकसित होलोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया। आईपीए के प्रोफेसर स्टीफन बोर्मेन और मैक्स प्लैंक के निदेशक ने बताया कि अगर हम इन प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त वर्षा के सूक्ष्म पहलुओं को तूफान और बादलों के विश्लेषण के लिए उपयोग किए गए मॉडल पर लागू करते हैं, तो हम बेहतर अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या करेंगे। बोर्मेन ने जोर देकर कहा, सूखा और भयंकर बारिश जैसी चरम मौसम की घटनाओं में होने वाली वृद्धि को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के हर हिस्से में भी होगा। हाइड्रोक्वैमेट के निष्कर्षों की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञों ने मैन्ज और संबंधित प्रकाशनों में किए गए प्रयोगशाला प्रयोगों के बहुत सकारात्मक मूल्यांकन प्रदान किए। उन्होंने मौसम की सटीक जानकारी के लिए विशेष रूप से उपलब्ध बुनियादी ढांचे, यानी वर्टिकल विंड टनल द्वारा निर्भाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया

किस तरह हो आर्द्रभूमि में सुधार, क्या हैं नए तरीके

यह अध्ययन प्रदूषित जल मागों से विषाक्त पदार्थों को हटाने और शहरी आर्द्रभूमि में सुधार करने के लिए अहम जानकारी प्रदान करता है। अध्ययन में मिट्टी और पानी में पीएफएस को कम करने में सक्षम एक आर्द्रभूमि में उगने वाले पौधे की खोज की गई है। वहीं दूसरी ओर गर्मियों के दौरान शहरी आर्द्रभूमि के जल प्रवाह के बेहतर प्रबंधन के बारे में भी पता लगाया गया है। अध्ययनकर्ताओं ने एक प्लास हाउस प्रयोग के अपने पहले अध्ययन में एक आम आर्द्रभूमि में उगने वाले पौधे की खोज की। यह पौधा प्रमुख प्रदूषक पेरफ्लूरोआकाइल और पॉलीफ्लूरोआकाइल पदार्थों (पीएफएस) को सहन कर उन्हें कम करने में सक्षम पाया गया। यहां बताते चलें कि पेरफ्लूरोआकाइल और पॉलीफ्लूरोआकाइल पदार्थ (पीएफएस) पीने के पानी, खाद्य पदार्थों, खाद्य पैकेजिंग सामग्री और अन्य उपभोक्ता उत्पादों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। सामान्य प्रजनन कार्य और हार्मोनल सिग्नलिंग में बदलाव करने की उनकी क्षमता के आधार पर कई पीएफएस को हार्मोन खचित करने वाले रसायनों के रूप में पहचाना गया है। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि वेटलैंड में उगने वाला पौधा जंकस सरोफोरस में पीएफएस को सहन करने की अधिक क्षमता है और एक समय में यह 9 से 11 फीसदी के बीच पीएफएस को हटाने में सक्षम है, जिसे पानी के स्तर में फ्लोटिंग रीड बेड के साथ बढ़ाया जा सकता है। डॉ. इल्का वालिस ने कहा यह पीएफएस को जमा करने में भी प्रभावी है। पीएफओए और पीएफएचएसएस को मिट्टी से ऊपर-जमीन के वनस्पति बायोमास में स्थानांतरित कर सकता है। डॉ. इल्का वालिस फिलंडर्स यूनिवर्सिटी हाइड्रो जियोलॉजिस्ट हैं। इस पौधे के तेजी से बढ़ने की दर के साथ, यह पौधा छोटी श्रृंखला वाले पीएफएस यौगिकों को छानने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है, लेकिन इस यौगिक की लंबी श्रृंखला-लंबाई और मिट्टी द्वारा अवशोषित होने की क्षमता के कारण पीएफओएस को हटाने में यह कम प्रभावी है। दुनिया भर के वातावरण में पीएफएस भारी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए स्थानीय स्तर पर प्रभावी उपायों, उपचार के समाधानों की तत्काल आवश्यकता है। सह-अध्ययनकर्ता और पर्यावरण स्वास्थ्य शोधकर्ता फिलंडर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हॉवर्ड फेलोफील्ड कहते हैं कि फाइटी-रेमेडिएशन पीएफएस के लिए एक संभावित उपचारात्मक रणनीति पेश करता है जो बड़े पैमाने पर कुशल और कम लागत वाले उपचार में मदद करता है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के दक्षिणी उपनगर में स्टॉर्मवॉटर-फेड वेटलैंड और जल उपचार स्थल पर पोषक तत्व और प्रदूषण के लिए तल पर उगने वाले पौधों और पानी का विश्लेषण किया गया था। मैक्रोफाइट्स के 36 इलाकों और पानी के 46 जगहों से नमूने एक व्यवस्थित तरीके से लिए गए। पानी के प्रवाह के आधार पर प्रत्येक इलाके चुना गया। कार्बन, नाइट्रोजन और अन्य तत्वों के लिए कुल 144 तने और जड़ों के नमूनों की जांच की गई, इनमें अमोनिया और कुल छोड़े गए टोस तत्वों के लिए पानी के 183 नमूने लिए गए। परिणामों में जल रसायन की अधिक मात्रा दिखाई दी, लेकिन मैक्रोफाइट के स्वास्थ्य में कमी और पौधे के द्वारा छाने गए टोस पदार्थ पाए गए, क्योंकि गर्मी के दौरान पानी का प्रवाह धीमा हो गया था। अध्ययनकर्ता विल्किंस कहते हैं कि हमारा अध्ययन वेटलैंड प्रबंधकों को सही डिजाइन करने, जल प्रवाह और वनस्पति नियंत्रण को समायोजित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ताकि पोषक तत्वों और दूषित पदार्थों को अलग-अलग करके एक साथ बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सके। विल्किंस ने बताया कि पानी का प्रवाह मैक्रोफाइट के छानने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसका प्रयोग दुनिया में कहीं भी आर्द्रभूमि के स्वास्थ्य और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। कुशल तरीके से छानने और तेजी से बहते पानी, कृषि अपवाह और औद्योगिक अपशिष्ट जल से नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और दूषित पदार्थों को हटाने से आसपास के वातावरण में संभावित हानिकारक प्रदूषकों की सीमा कम हो जाएगी। इससे शहरी और अन्य जगहों के आर्द्रभूमि में पानी की गुणवत्ता के उपचार तकनीकों में सुधार होगा। यह अध्ययन फिलंडर्स विश्वविद्यालय की अगुवाई में किया गया है।

समाप्त - डाकू द अर्थ